चीनी उद्योग को उबारने के लिए मैकेंजी का नुस्खा

- पक्षकारों को दिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुझाव
- मिलों पर बैंकों का 35 हजार करोड़ की भारी बकायेदारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : संकट के दौर से गुजर रहे चीनी उद्योग और गन्ना किसानों को उबारने के लिए इससे जुड़े सभी पक्षों को कारगर पहल करनी होगी। समय पर गन्ना किसानों का भुगतान, एथनॉल का उत्पादन बढ़ाकर चीनी उत्पादन पर नियंत्रण करने और घरेलू बाजार की जरूरतों के साथ निर्यात को प्रोत्साहित करने से उद्योग में सुधार हो सकता है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मैकेंजी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में इसी तरह के कई नुस्खे सुझाए हैं। उसने इसके लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक उपाय गिनाए है। रिपोर्ट में केंद्र सरकार के लिए सुझाव दिए गए हैं कि वह उचित व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) और चीनी के अंतर को खुद वहन करे। इसके लिए वह सीधे किसानों के खाते में पैसा जमा कराए। इसका दबाव मिलों पर नहीं होना चाहिए। इसी तरह राज्य सरकारों को चीनी कीमत और गन्ने के राज्य समर्थित मूल्य (एसएपी) का अंतर वहन करना चाहिए। चीनी मिलें भी किसानों के गन्ना भुगतान में देरी न करें।

चीनी मिलों की इस दशा के लिए गन्ना किसानों को भी जिम्मेदार बताया गया है। गन्ना खेती का लगातार बढ़ता रकबा और गन्ना मूल्य निर्धारण में अदूरदर्शिता के चलते यह मुश्किल पैदा हुई है। अन्य फसलों के मुकाबले गन्ने में चार गुना से अधिक का फायदा होने की वजह से ही किसान अधिक खेती करने लगा है। इसका दबाव मिलों पर पड़ना तय है। मैकेंजी ने सुझाव दिया है कि किसानों को भी गन्ने की खेती का रकबा सीमित करना चाहिए।

आंकड़ों का हवाला

- गन्ना मूल्य बकाया 14,500 करोड़ रुपये है
- इससे एक करोड़ किसान प्रभावित हो रहे हैं
- चीनी स्टॉक एक करोड़ टन तक अतिरिक्त हो सकता है
- 500 मिलों में से केवल 130 के पास ही डिस्टीलरीज हैं
- भारत में अब तक कुल 200 मिलें बंद हो चुकी हैं
- 12 मिलें घाटे की वजह से दिवालिया हो गई हैं
- उत्तर प्रदेश की कई मिलें पेराई न करने का नोटिस दे चुकी हैं
- बैंकों के चीनी की मिलों पर 35,000 करोड़ रुपये बकाया

Dainik Jagaran

12/8/15